

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, पुलिसकर्मी शहीद, हमलावरों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन

अनंतनाग (एजेंसी) जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकीयों ने पुलिस दल को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया। इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल शहीद हो गए। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकीयों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह हमला अनंतनाग जिले के कोक्करनाग क्षेत्र के लाल चौक के पास उस समय हुआ जब पुलिस की टीम नियमित ड्यूटी पर तैनात थी। इसी दौरान सदिग्ध आतंकवादियों ने अचानक पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिसकर्मीयों ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमले में हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक, घटना बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे हुई। घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास किया।



हनुमत विहार

26.643 हेक्टेअर में फैली यह टाउनशिप लैंड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत नियोजित की गई है। इस योजना में 26.68 प्रतिशत विकसित भूखंड भूस्वामियों को प्रदान किया गया है। योजना की अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय **₹. 194.04 करोड़** है।

इस आवासीय योजना में प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी ड्रा के माध्यम से 230 आवंटियों को किया जा चुका है। एमवीडीए द्वारा इस योजना के तहत व्यावसायिक, गुप हाउसिंग और संस्थागत प्लॉटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

गोविंद विहार

26.912 हेक्टेअर में फैली यह टाउनशिप लैंड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत नियोजित की गई है। इस योजना में 26.68 प्रतिशत विकसित भूखंड भूस्वामियों को प्रदान किया गया है। योजना की अवस्थापना सुविधाओं पर होने वाला व्यय **₹. 182.23 करोड़** है।

इस आवासीय योजना में प्राधिकरण के आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी ड्रा के माध्यम से 121 आवंटियों को किया गया है।

ग्रीनफील्ड टाउनशिप – छाता

117.295 हेक्टेअर में प्रस्तावित यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप ग्राम छाता में विकसित की जा रही है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत **₹. 1265.00 करोड़** है, जिसमें अवस्थापना सुविधाएं, सड़क, जल, सीवर, विद्युत एवं सार्वजनिक उपयोग की अन्य संरचनाएं शामिल हैं।

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा
राजकीय संग्रहालय, डैमियर नगर, मथुरा
Email: vcmda2014@gmail.com | Website: www.mvdamathura.com

Follow us on
f i x

सीएम योगी ने किया निर्देशित जलभराव की समस्या बर्दाश्त नहीं, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

सीएम योगी बुधवार दोपहर एनेक्सी भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जलनिकासी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उनका सर्वाधिक जोर जलनिकासी को लेकर रहा। उन्होंने दो दूक कहा जो भी जरूरी तैयारी या व्यवस्थाएं करनी हैं, उन्हें सुनिश्चित किया जाए, कहीं भी और किसी भी दशा में जलभराव नहीं दिखना चाहिए।



लेत हुये कहा कि नालों की नियमित रूप से सफाई हो। सफाई के बाद उन्हें ढका जाए। कहीं भी नालियां खुली न रहें। नगर निगम के सभी पंप पूरी क्षमता से संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों को प्रेरित किया जाए कि वह कूड़ा नालियों में न डालें। स्वच्छता के लिए कार्यक्रम चलाया जाए, साथ ही नियमित छिड़काव एवं फागिंग कराई जाए। सीएम ने कहा कि जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में एंटी स्नैक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध रहे।

की सफाई कराई जाए और कूड़ा निस्तारण सही से किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया जाए और इसे रूटीन के कार्यों का हिस्सा बनाया जाए। कहा कि स्वच्छता के कार्यक्रम के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। शासकीय भवनों में भी सफाई पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने, स्ट्रीट लाइटों को ठीक रखने और सभी सीसीटीवी को अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा गोवंश सड़कों पर न रहें। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि डॉंग सड़कों पर न रहें। उनके लिये डॉंग शेल्टर बनाया जाए। सीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में एंटी स्नैक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध रहे।

सीजेपी का इन्स्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार पर लगाया आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी) पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बुधवार को दावा किया कि केंद्र ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि छम्पे पेपर लीक के मामले में जवाबदेही तय करने की कोशिशों के तहत, वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का भरोसा देती है, तो वे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। सरकार को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा मैं सरकार से साफ-साफ भरोसा चाहता हूं कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या बदले की भावना वाली कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनका एकमात्र अपराध एक निष्पक्ष



ओर जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज उठाना रहा है। एजिक््यूटिव ब्रांच दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ब्रिच मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की।

अनशन खत्म करने को तैयार हुए सोनम वांगचुक, लेकिन सरकार के सामने रख दी ये बड़ी शर्त



सोनम वांगचुक ने सरकार से छान आत्महत्याओं के मुआवजे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर संसद में चर्चा और युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के स्पष्ट आश्वासन पर अपना अनशन खत्म करने की बात कही है। यह प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद आया है, जो पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छान आंदोलन का अहम मोड़ है।

नई दिल्ली (एजेंसी) एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को पत्र लिखा है। अपने पत्र के साथ एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सरकार से अपील। मेरा अनशन तोड़ने के संबंध में... एक बार सरकार से आश्वासन मिल जाने के बाद, मैं शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों से भी अपील करूंगा कि वे फिलहाल आंदोलन रोक दें और सरकार के साथ बातचीत शुरू करें। वहीं, पत्र में लिखा है कि कल रात अस्पताल में मुझे मिलने और मेरा अनशन खत्म करने की आपकी ईमानदार अपील के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही वांगचुक ने कहा कि हमारी बातचीत के दौरान, आपने मुझे भरोसा दिलाया कि सरकार उन छात्रों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी जिन्होंने परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद

आत्महत्या कर ली थी, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसद में सार्थक चर्चा होगी, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करना भी शामिल है। मैं सरकार से सम्मानपूर्वक यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र अपराध एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली के लिए आवाज उठाना रहा है।

एससी का बड़ा निर्देश: जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 61 साल करने पर विचार करें राज्य, एससी ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट



नई दिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें। साथ ही, कोर्ट देश भर में इसे एक समान रूप से 62 साल करने की मांग वाली याचिका पर भी विचार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह अंतर्निहित व्यवस्था 1 अप्रैल से उन जगहों पर लागू होगी, जहाँ राज्य सरकार और संबंधित हाई कोर्ट इस कदम पर सहमत होंगे। चीफ जस्टिस सुर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने हाई कोर्ट से सलाह करके इस फैसला लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि इस अस्थायी इंतजाम का उस अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसमें यह तय होना है कि क्या पूरे देश में जिला न्यायपालिका के जजों की रिटायरमेंट की उम्र एक समान रूप से 60 से बढ़ाकर 62 साल की जानी चाहिए या नहीं। अपने आदेश में बेंच ने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (न्हे) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मुद्दे पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट से सलाह करके फैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। सेवा में बने रहने की यह अनुमति इन कार्यवाही के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि वे हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद दो हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखें। संबंधित हाई कोर्ट से भी कहा गया है कि वे इसी समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। हालांकि, जो राज्य और हाई कोर्ट पहले से ही इस बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं, उन्हें विस्तृत जवाबी हलफनामे के बजाय केवल सहमति का एक संक्षिप्त बयान दाखिल करना होगा। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं।

आपरेशन यात्री सुरक्षा में आरपीएफ-जीआरपी को बड़ी सफलता, डेढ़ लाख से अधिक कीमत के दो चोरी के मोबाइल बरामद



संवाददाता
प्रयागराज, । प्रयागराज मंडल के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे श्ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) एवं राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की संयुक्त टीम ने एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 1.75 लाख रुपये मूल्य के दो चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं।रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार प्रमारी निरीक्षक आरपीएफ अलीगढ़ के नेतृत्व में 21 जुलाई को आरपीएफ एवं जीआरपी की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या-7 स्थित लिफ्ट के सामने टीन शेड के नीचे संदिग्ध अवस्था में मौजूद एक युवक को पकड़कर पूछताछ की गिरफ्तार आरोपी की पहचान आतिफ (24 वर्ष) पुत्र दिलशाद, निवासी बरगद हाउस, थाना सिविल लाइन, जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई। तलाशी

जौहर यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन



संवाददाता
गोरखपुर, । रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के विरोध में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को मंडलायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय केध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा वहां अध्यक्षनरत हजारांछात्र-छात्राओंकेभविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनेकी मांग की।समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव फुसुमद आसिम

खान के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि मौलाना मेहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शामिल है और इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा।मुहम्मद आसिम खान ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना मेहम्मद अली जौहर के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के 40 में से 38 बच्चों को ध्वस्त करने के निश्चय दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के मानचित्र संभ्रं गी धिंवद को आखर बनाकर की जा रही कार्रवाई उचित नहीं है और इस पर तत्काल

रोक लगनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप कर विश्वविद्यालय को संरक्षित रखने छात्रों की पढ़ाई निरुद्ध जारी रखने तथा उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के प्रसार की बात करने वाली सरकारों को ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। इस अवसर पर पंढर दल के नेता अशोक यादव, पंढर शहाब अंसारी, पूर्व पंढर कुल्लू अली, इस्लामिक अहमद बकू शकील अहमद अंसारी, हाजी कलीम अहमद फरजंद, अनवर आलम नबीउल्लाह अंसारी, दिलीप कुमार निषाद सहित अन्य वक्ताओं ने भी विश्वविद्यालय को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया। ज्ञापन रौमने के दौरान मुर्तजा हुसैन रहमानी, अमय गुप्ता, रंजु लारी, मेहमूद असलम, अतिफ खान, हसनैन अहमद, अमय सिंह, मेनु सिंह, अमिष्क पांडेय, भीम निषाद, विजय शर्मा रणजीत सिंह, विकास राय, राजेश कुल्ला, अशोक गुप्ता, रंदि गुप्ता, सुस्तान खान, राजेंद्र कनैजिया, राजन, दिलीप प्रसाद, मेहम्मद जाकिर, फराज रिश्दीकी, जब्बार राजन जोसवा, मेहम्मद नवाज हुसैन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण नोटिस रद्द करने तथा दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में सीरत वेलफेयर कमेटी ने दिया ज्ञापन



संवाददाता
बहराइच, । सामाजिक संगठन सीरत वेलफेयर कमेटी (पंजीकृत) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को जारी ध्वस्तीकरण नोटिस निरस्त करने तथा दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं और युवाओं पर हुए कथित लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय जांच की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।कमेटी के सचिव शादाब हुसैन ने कहा कि सरकार एक ओर शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के विस्तार की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के संचालन के वर्षों बाद उसकी इमारतों को लेकर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया जाना हजारों छात्रों के भविष्य और कर्मचारियों के रोजगार पर संकट पैदा करता है। उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय को नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का अवसर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं युवाओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए

के घटनाक्रम पर भी आपत्ति जताई।पन के माध्यम से संगठन ने मांग की कि रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस पर तत्काल रोक लगाई जाए, विश्वविद्यालय को नियमानुसार नक्शा स्वीकृत कराने एवं शमन की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर दिया जाए, ताकि छात्रों की शिक्षा और कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित रह सके।इसके अलावा संगठन ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई की उच्चस्तरीय जांच, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, पेपर लीक प्रकरण में जिम्मेदारी तय करने, प्रदर्शन के दौरान मृत एवं घायल लोगों के लिए आर्थिक सहायता तथा बेरोजगार युवाओं को रोजगार अथवा भत्ता दिए जाने की भी मांग की।इस अवसर पर डॉ. अजीमुल्ला खान, मौलाना शाहिद नदवी, मौलाना सरवर कासमी, मौलाना शाहिद अख्तर, शकील मिर्ज़, शादाब अंसारी, शेख रियाजुद्दीन एडवोकेट, वसीउल्ला कासमी, हाजी आसिफ खान, सैय्यद अकरम सईद, मो. शुएब, मुबीन अहमद, रियाजुद्दीन खान, राजकुमार यादव, रिक्कू यादव एवं वली मोहम्मद सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत, बच्चों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक: इकरा सईद



लखनऊ, । मसरूर एजुकेशनल सोसायटी के तत्वावधान में सेंट रोज पब्लिक स्कूल, गढ़ी पीर खां, ठाकुरगंज में जल संचयन एवं जल संरक्षण विषय पर एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य प्रो. अतीक अहमद फारूकधी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप

में इकछरा सईद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (क्लाइमेट प्रचर्चा) एवं फैंशन डिजाइनर, उपस्थित रहें। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। डॉ. मनसूर हसन खां ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि संचालन शीबा खान ने किया। सेमिनार में सुराशत उपाध्याय, शिवाजी, अरदुल्ला, सारा और आयुष कुमार चौधरी ने जल संरक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि इकछरा सईद ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसका कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा कि भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पानी का संरक्षण करे और उसकी एक-एक बूंद का सदुपयोग सुनिश्चित करे।अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रो. अतीक अहमद फारूकधी ने कहा कि भविष्य में जल संकट से बचने के लिए समाज में व्यापक जनजागरूकता आवश्यक है। विशेष रूप से बच्चों को जल संरक्षण के प्रति शिक्षित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने जल संरक्षण पर गीत, दोहे, गजल और प्रेरक विचार प्रस्तुत किए।

मानसून को लेकर उत्तर मध्य रेलवे अलर्ट, महाप्रबंधक ने संरक्षा तैयारियों की समीक्षा की फील्ड निरीक्षण बढ़ाने और सवेदनशील रेलखंडों पर विशेष निगरानी के निर्देश



। कराई जा सके।

प्रयागराज, । मॉनसून के दौरान ट्रेनों का सुरक्षित एवं निर्बंध संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर मध्य रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यालय के विभागाध्यक्षों तथा तीनों मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।बैठक में महाप्रबंधक ने कहा कि बारिश के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्था मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए संस्थित जेखिम वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा रेल परिचालन में बाधा की स्थिति उत्पन्न न हो।उन्होंने फील्ड अधिकारियों को केवल कार्यालयी समीक्षा तक सीमित न रहकर सवेदनशील रेलखंडों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही अपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मॉनसून वैगनों को पूरी तरह तैयार रखने को कहा।महाप्रबंधक ने भारी वर्षा एवं फ्लैश फ्लड की संभावनाओं को देखते हुए रेल पुर्णों, नदियों और नालों के आसपास विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में तत्काल निगरानी और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि ट्रैक और रेल यातायात प्रभावित न हो।बैठक में रेलवे ट्रैक की स्थिरता बनाए रखने के लिए बेकारस्ट ड्रेनेज सिस्टम तथा सिग्नलिंग व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ट्रैक के आसपास जलमयार रोकने, सिग्नलिंग फेल्चर की आंशका कम करने तथा रखरखाव टीमों को 24 घंटे सतर्क रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।महाप्रबंधक ने कहा कि मॉनसून के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और निर्बंध रेल यात्रा उपलब्ध

रेलवे स्टेशनों पर गूंजेगे जागरूकता गीत सुरक्षा और स्वच्छता का देगे सदेश



खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए सजगता और सवेदनशीलता जरूरी : सरदार पतविंदर सिंह धान रोपाई कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर दिया अन्न संरक्षण का सदेश



प्रयागराज, । भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने बुधवार को अपने सहयोगियों

संवाददाता

प्रयागराज, । रेल यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और जिम्मेदार यात्रा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर मध्य रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर विशेष जागरूकता गीत प्रसारित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से यात्रियों को रेल सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जाएगा।इस अभियान की खास बात यह है कि जागरूकता गीत दो बाल कलाकारों आरव (9 वर्ष) और अरित (13 वर्ष) ने तैयार किया है। प्साई बंधू के नाम से प्रसिद्ध दोनों भाइयों ने अपनी मधुर आवाज के माध्यम से यात्रियों को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, स्वच्छता बनाए रखने और यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश दिया है।गीत में यात्रियों से ट्रेनों पर पथखाबी न करने, रेलवे परिसर में कूड़ा-कचरा न फैलाने, किसी अजनबी से खाने-पीने की वस्तु स्वीकार न करने तथा सुरक्षित एवं जिम्मेदार यात्रा करने की अपील की गई है। रेलवे का मानना है कि इस तरह के रचनात्मक प्रयास यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेंगे।उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने कहा कि बच्चों द्वारा प्रस्तुत इस प्रकार के रचनात्मक प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि यह जागरूकता गीत यात्रियों तक सुरक्षा और स्वच्छता का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाएगा तथा सभी को सुरक्षित, स्वच्छ और जिम्मेदार रेल यात्रा के लिए प्रेरित करेगा।गीत के माध्यम से यात्रियों से आह्वान किया गया है कि वे भारतीय रेल को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं तथा रेलवे की संपत्ति की रक्षा करते हुए सुरक्षा नियमों का पालन करें।

उन्होंने लोगों से अन्न के प्रत्येक दाने का सम्मान करने और भोजन की बर्बादी रोकने का संकल्प लेने का आह्वान किया।इस अवसर पर सरदार पतविंदर सिंह ने कहा कि अन्न जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन आज भी दुनिया भर में बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर दिखावे की संस्कृति ने भोजन की बर्बादी की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोग भूख और कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए समाज में सजगता और संवेदनशीलता दोनों का होना आवश्यक है।श्रीमती दलजीत कौर ने

कहा कि प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में भोजन व्यर्थ चला जाता है और बदलती जीवनशैली के कारण यह समस्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भोजन की बर्बादी केवल अन्न का नुकसान नहीं, बल्कि पानी, ऊर्जा, श्रम और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी बर्बादी है, क्योंकि भोजन उत्पादन से लेकर पकाने तक अनेक संसाधनों का उपयोग होता है।परमजीत सिंह बग्गा ने कहा कि भोजन की बर्बादी रोकने में आमजन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आवश्यकता के अनुसार ही भोजन लेने और थाली में जूठन न छोड़ने की आदत विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब एक ओर भोजन फेंका जा रहा होता है, तब दूसरी ओर करोड़ों लोग भूख पेट सोने को मजबूर होते हैं।कोशल किशोर सिंह ने कहा कि भोजन की बर्बादी किसान की मेहनत का भी अनादर है। किसान कठिन परिस्थितियों में परिश्रम कर अन्न पैदा करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी थाली में परसे गए हर दाने का सम्मान करना चाहिए।कार्यक्रम के दौरान धान की रोपाई कर रहे किसानों एवं ग्रामीणों को भोजन की बर्बादी न करने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर सरदार पतविंदर सिंह, दलजीत कौर, परमजीत सिंह बग्गा, कोशल किशोर सिंह सहित अनेक स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जनसुनवाई में सुनीं महिलाओं की समस्याएं

प्रयागराज, । उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने बुधवार को सर्वेंट हाउस सभागार में आयोजित जनसुनवाई में महिलाओं की समस्याएं सुनीं। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई 26 महिलाओं ने अपनी शिकायतें आयोग के समक्ष प्रस्तुत की, जिन पर सदस्य ने संबंधित अधिकारियों को सम्यबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।जनसुनवाई में विभिन्न कारियों को सम्यबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।जनसुनवाई के दौरान गीता विश्वकर्मा ने कहा कि राज्य महिला आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और सम्मान दिलाना भी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि छोटे-मोटे मामलों का निस्तारण यथारंभ तथा स्तर पर ही किया जाए, ताकि पीड़ित महिलाओं को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।उन्होंने कहा



कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं और बालिकाओं तक सम्यबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।जनसुनवाई में विभिन्न मामलों पर भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। करछना क्षेत्र में भूमि पर कथित अंधे कब्जे की शिकायत पर एसडीएम करछना को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। नैनी क्षेत्र की एक महिला द्वारा पति के परिवार पर मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न तथा पति की गुमशुदगी के कारणों से थानाध्यक्ष नैनी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।इसी प्रकार धूमनगंज क्षेत्र की एक महिला की शिकायत पर थानाध्यक्ष को कथित जानलेवा हमले

राजस्व परिषद के अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज, आज से क्रमिक अनशन पर बैठेंगे

प्रयागराज, । अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कथित असंवैधानिक आदेश के विरोध में बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के समर्थन में बुधवार को प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशनों के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। संगठन ने घोषणा की है कि 23 जुलाई से अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, जबकि आगे की रणनीति आमसभा में तय की जाएगी।बार एसोसिएशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तत्वावधान में राजस्व परिषद परिसर में विशाल धरना-प्रदर्शन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें

हाँडिकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद, जनपद न्यायालय बार एसोसिएशन, कमिश्नरी बार एसोसिएशन प्रयागराज, कानपुर बार एसोसिएशन, आजमगढ़ बार एसोसिएशन, विन्ध्याचल मंडल बार एसोसिएशन सहित विभिन्न मंडलों, जिलों और तहसीलों के अधिवक्ताओं ने भाग लेकर आंदोलन को समर्थन दिया।बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बालकृष्ण पाण्डेय ने की, जबकि संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश राय ने किया। इस दौरान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के संयुक्त सचिव (पुस्तकालय) शशि कुमार द्विवेदी श्रुग्रह ने हाईकोर्ट बार की ओर से समर्थन पत्र

सौंपते हुए आंदोलन के प्रति एकजुटता व्यक्त की।जिला बार एसोसिएशन के मंत्री वरुण सिंह तथा कमिश्नरी बार एसोसिएशन प्रयागराज के अध्यक्ष सुधीर श्रीवास्तव और महामंत्री मुकेश नारायण त्रिपाठी ने भी आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अहिंसात्मकता की मांगों को न्यायोचित बताया।बार एसोसिएशन के महासचिव अनिरुद्ध शर्मा ने कहा कि संगठन अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ेंगा और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।संयुक्त सचिव (प्रेस) सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि अधिवक्ता न्यायिक

कार्य से विरत रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का बहिष्कार तथा तालाबंदी जैसे कदम उठाकर आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 23 जुलाई को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू परिसर में आमसभा आयोजित होगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी।इस अवसर पर शैलेन्द्र कुमार सिंह, रमेश पुण्डीर, कल्लन उर्फ विजय शंकर तिवारी, अरुणेश खरे, राजेश प्रताप सिंह, सुनील वर्मा, रोहित शर्मा, सूर्यकांत शर्मा, नवीन कुमार पाण्डेय, शरद कुमार पाण्डेय, अम्बुज श्रीवास्तव, ब्रजभूषण पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

चंद्रशेखर आजाद ने देश की आजादी के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया : राजेश केसरवानी

120वीं जयंती की पूर्व संंध्या पर चला शहर घर आजादर जागरण अभियान, वितरित किए गए चित्र



परिचित कराना समय की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से शहर घर आजादर अभियान के तहत लोगों को चंद्रशेखर आजाद के चित्र वितरित किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक घर में उनकी प्रेरणादायी छवि युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रसेवा की भावना का संसार करती रहे। कार्यक्रम का संचालन शत्रुज्ज जायसवाल ने किया, जबकि अभिलाष केसरवानी संयोजक रहे।इस अवसर पर किशन चंद्र जायसवाल, सुनील केसरवानी (सेनू), अशोक गुप्ता, राजेश गुप्ता, श्याम कृष्ण विश्वकर्मा, मुकेश जायसवाल, नीरज केसरवानी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि गुप्त के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पांच दिनों से अंधेरे में वरिष्ठ पत्रकार का घर, बिजली बहाली के लिए शिवत मांगने का आरोप

प्रयागराज, । झूरी (द्वितीयः ग्रामीण) विद्युत् वितरण उपखंड के अंतर्गत बलरामपुर पावर हाउस क्षेत्र के मंडौर गांव में वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र सिंह के आवास पर पिछले पांच



दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर बिजली जोड़ने के बदले सुविधा शुल्क (रिश्कत) मांगने तथा शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया है।नागेंद्र सिंह के अनुसार उन्होंने विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत संख्या च22072607998 दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद लाइनमैन मौके पर पहुंचे और पोल पर चढ़कर जांच भी की, लेकिन कथित रूप से सुविधा शुल्क की मांग की। आरोप है कि मनमाफिक रकम नहीं मिलने पर लाइनमैन छद्मूटी समाप्त होने की बात कहकर बिना बिजली बहाल किए लौट गया।पीड़ित का यह भी आरोप है कि विभाग लंबे समय से वास्तविक खपत की तुलना में अत्यधि ाक बिजली बिल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि मीटर में गड़बड़ी की लिखित शिकायत पहले ही संबधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो

सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि नए कनेक्शन के समय विभाग द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराया जाने वाला सरकारी सर्विस केबल भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका कहना है कि उपभोक्ता नियमित रूप से बिजली बिल, फिक्स चार्ज और अन्य शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

इस मामले को लेकर राज्य मुख्यालय के पत्रकारों एवं स्थानीय नागरिकों ने भी नाराजगी जताते हुए ऊर्जा मंत्री और विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने शिकायत संख्या च22072607998 का शीघ्र निस्तारण कर बिजली आपूर्ति बहाल करने, मीटर एवं बिलिंग की निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सीटों की कटौती, फीस वृद्धि और मूलभूत सुविधाओं को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा जापन



प्रयागराज, । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई ने बुधवार को छात्रों की शैक्षणिक, आर्थिक एवं मूलभूत समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष विभिन्न मांगें उठाईं। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रो. आशीष खरे एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण (डीएसडब्ल्यू) डॉ. सूर्यभान सिंह को अलग–अलग ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की।कुलसचिव को सौंपे गए ज्ञापन में परिषद ने स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में पूर्व में की गई सीटों की कटौती को

तत्काल बहाल करने तथा फीस में हुई वृद्धि को वापस लेकर विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप करने की मांग की। इकाई अध्यक्ष हिमांशु पाण्डेय ने कहा कि सीमित सीटों और बढ़ी हुई फीस के कारण बड़ी संख्या में मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने पीजीएटी–2026 के परिणाम एवं कटऑफ जारी होने के मद्देनजर सीटों की बहाली पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।डीएसडब्ल्यू को सौंपे गए ज्ञापन में विश्वविद्यालय परिसर की मूलभूत सुविधाओं सुधार की मांग करते हुए प्रत्येक संकाय में छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट, महिला कॉमन

प्रयागराज, । अमर क्रांतिकारी श्रद्धांजलि गुप्त की ओर से महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती की पूर्व संंध्या पर शहर घर आजादर जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि समा आयोजित कर लोगों को चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व एवं राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान से अवगत कराया गया तथा उनके चित्र वितरित किए गए।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि गुप्त के अ्यक्ष राजेश केसरवानी ने कहा कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जाति–पात और संकीर्ण विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म माना। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के अनुरूप अंतिम सांस तक श्आजादर रहे और मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्रयागराज की ऐतिहासिक धरती पर वीरगति को प्राप्त हुए।राजेश केसरवानी ने कहा कि नई पीढ़ी को देश के महान क्रांतिकारियों के त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति से

छात्रों और राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी



संवाददाता प्रयागराज, । प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी एवं अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुवार को पथर गिरिजा धरना स्थल से सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहा तक आक्रोश मार्च निकालकर छात्रों एवं लोकसभा में नेता

प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कथित दुर्घ्यवहार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकतांत्रिक अधिाकारों की रक्षा की मांग उठाई।प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी

ए आई तकनीकी उपकरण, लेकिन भाषा की संवेदना और भारतीय चिंतन को संरक्षित करना जरूरी : सर्वेश पांडे

प्रयागराज, । हिन्दुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में बुधवार को गांधी समागार में ‘आधुनिक परिवेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भाषा’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।एकेडेमी के सचिव डॉ. अजीत कुमार सिंह ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रभाव अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वास्तविक साहित्य मानवीय संवेदना से जन्म लेता है, जबकि एआई उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर सामग्री तैयार करता है। इसलिए दोनों के बीच मूलभूत अंतर को समझना आवश्यक है।संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए प्रो. शर्कषा पाण्डेय, प्राचार्य, डी.सी.एस.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊ ने कहा कि वर्तमान समय एआई का युग है और भाषा के क्षेत्र में यह अवसर का साथ–साथ चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि हिन्दी

पेपर लीक मुद्दे पर दिल्ली कूच से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद सहित कई नेता नजरबंद

राष्ट्रपति के नाम धाना प्रभारी को सौंपा जापन, कार्रवाई को बताया लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन



प्रयागराज, । पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित दिल्ली महाप्रदर्शन से पूर्व प्रयागराज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशफाक अहमद सहित कई पदाधिकारियों को उनके आवासों पर नजरबंद कर दिया जाने का दावा किया गया। इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन धाना प्रभारी बहरिया को सौंपकर कार्रवाई पर आपत्ति जताई।कांग्रेस नेताओं के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, प्रदेश

छात्रों के आंदोलन के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी, सरकार संवाद के बजाय दमन कर रही : सुप्रिया श्रीनेत

प्रयागराज, । कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि देशभर में छात्रों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कांग्रेस पार्टी छात्रों की न्यायोचित मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज को हर स्तर पर उठाती रहेगी।बुधवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रीनेत्र ने आरोप लगाया कि संसद मार्च में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे हजारों छात्र–युवा सरकार से संवाद और अपनी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा लेकर आए थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज



किया गया, कई छात्र घायल हुए तथा महिला छात्रों के साथ दुर्घ्यवहार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आईं।उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखने तथा उनसे मुलाकात करने के

और आम जनता के अधिकारों की लड़ई सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रही है। पुलिस प्रशासन के दबाव में जनआवाज को दबाया नहीं जा सकता।वहीं वरिष्ठ पार्षद तस्लीम उद्दीन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता के अधिकारों और न्याय की लड़ई को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मप्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की।आक्रोश मार्च एवं प्रदर्शन मेंप्रमुख रूप से शैक्षर बहुगुणा, तस्लीम उद्दीन, आबदी हसन, मो. हसीन, मनोज पासी, शकील अहमद, गजली खान, नरेंद्र गिरी, मो. जाहिद, मो.अल्टमस, महफूज अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोई अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग केवल निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा युवाओं के भविष्य की सुझा सुनिश्चित करने की है। उनका कहना था कि सरकार को दमनात्मक कार्रवाई के बजाय छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी देशभर में अपने अभियान के तहत 125 स्थानों पर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है और हर स्तर पर उनके अहिाकारों एवं हितों की रक्षा के लिए।श्रीनेत्र ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण विरोध के संकैानिक अधिकार पर सीधा प्रहार है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि छात्र

प्रयाग व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने पीडीए सचिव से की मुलाकात, शहर की प्रमुख समस्याओं से कराया अवगत



संवाददाता प्रयागराज, । प्रयाग व्यापार मंडल एवं जिला महिला व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के सचिव विनीत कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट कर शहर की विभिन्न नागरिक एवं व्यापारिक समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में शहर के विकास कार्यो व्यापारियों की समस्याओं तथा उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक के दौरान प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा चावला ने सचिव विनीत कुमार सिंह का पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद आयोजित परिचयात्मक बैठक में प्रयाग व्यापार मंडल एवं जिला महिला व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया।प्रतिनिधिमंडल ने पीडीए द्वारा निर्मित सड़कों पर जलभराव की समस्या, झूरी क्षेत्र में विकसित ग्रीन बेल्ट के सुधार कार्य, सुलेभसराय से कानपुर रोड तक बाजारों के बाहर अनियमित पट्टरी दुकानों के कारण उत्पन्न पार्किंग समस्या, आम नागरिकों को पीडीए की सड़कों एवं जोन कार्यालयों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा नक्शा पास एवं एनओसी के नाम पर व्यापारियों के कथित उत्पीड़न जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।पीडीए सचिव विनीती कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े सभी मुद्दों पर प्राथमिकता के

कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ के नाम से जाना जाएगा

प्रयागराज, । भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के जम्मू मंडल स्थित कठुआ (ड़जन्म) रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्हाहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ र्क कर दिया है। यह परिवर्तन उत्तरी रेलवे द्वारा 21 जुलाई 2026 को जारी अधिासूचना के अनुसार तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।रेल प्रशासन के अनुसार रेलवे की टिकटिंग प्रणाली (यूटीएसध पीआरएस) में स्टेशन का नाम अंग्रेजी में ‘डंतजलत ब्वंजपद नंदपस ज्ञनउत्त बीवनकींतल ज्जीन’ (डहंन्छप् ज्ञ ज्जन्म) तथा हिंदी में ‘शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ प्रदर्शित होगा। स्टेशन का नया कोड डैज्ञज निर्धारित किया गया है।रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा आरक्षण, टिकट बुकिंग एवं अन्य रेलवे सेवाओं का उपयोग करते समय स्टेशन के नए नाम और नए कोड डैज्ञज का ही प्रयोग करें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।रेल प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिक शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी की स्मृति को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। स्टेशन का नया नाम उनके अदम्य साहस, वीरता और देश के प्रति समर्पण को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किया गया है।



महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बिखराव की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि शरद पवार के आंगन में एक और दीवार खड़ी होती दिख रही है। भाजपा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन में राय दे रही हैं। वे इस बिल का समर्थन कर रही हैं लेकिन रोहित पवार ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। राजनीतिक गलियारों

सम्पादकीय आगे कुँआ, पीछे मोदी

बेचारे हिन्दू दोहरी चोट झेल रहे हैं कृ संघ–परिवार का विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग। क्या इस से आगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, राजा बाबू ने सब प्रबंध कर लिया है। कहीं कोई छिद्र नहीं छोड़ा। चुनावी फुटबॉल का नेशनल कप वही जीतते रहेंगे। बाकी इंडिया बस वाचता रहेगा! यह सब समाज को खोखला करतें जाने की कीमत पर। बस कप हाथ में रहे, चाहे वास्तविक खेल केवल कागजी हो जाए।

एक अर्थ में यह संघ–परिवार का ही तर्क है। तेईस साल पहले, 2003 में इसे श्टीनाघ (ज़ुज़दब़्द) कहा गया था कृ देयर इज नो अल्टरनेटिव कृ यानी, भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, ऐ देशवासियो, भाजपा को समर्थन दो! क्योंकि और किसे दोगे? कांग्रेस नेता को तो बोलना भी नहीं आता, कागज देख–देख पढ़ती है। बल्कि, जब तक यह बेचारी कांग्रेस की नेता है कृ तब तक भाजपा को चिन्ता की भी जरूरत नहीं! कौन श्इंडिया शाइनिंग्घ कर देने वाली भाजपा के बदले उस अटपटी कांग्रेस नेता को समर्थन देगा!

उक्त दलील 2004 के आरंभ तक इतनी दुहराई जाती रही थी, कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस वर्ष चुनाव से पहले कहा छुनाव में क्या होना हैय कोई कांटीशन ही नहीं है!

तब से भाजपा नेता काफी बदल गये हैं। कुछ मामलों में अिह क होशियार, कुछ मामलों में और माशाअल्लाह। अगला चुनाव जीतने वाली सब तकनीकी कमियाँ इन्होंने दूर कर ली हैं, जिन पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था। जिस में मुख्य यह कि मैघ जीतने का सब से सुप्रसिद्ध तरीका है कि सामने कोई टीम ही न हो। यानी, सामने टीम न बनने दो! प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों में किसी को लुमा कर, किसी को डरा कर, किसी को फँसा कर, उस टीम से दूर रखो जो चुनौती दे सकती हो। अपनी टीम में भी कैप्टन बनने योग्य खिलाड़ियों को बाहर कर दो। बस, घुमा–फिरा कर वह वातावरण बनानाकृ जिसे श्टीनाघ कह लीजिए कृ कि भई और है कौन जिसे समर्थन दोगे!

दूसरी ओर, माशाअल्लाह यह कि दस वर्ष पहले संघ–भाजपाइयों द्वारा जो ऊँची–ऊँची उपलब्धि की बात कही जाती थी, अब उन में किसी का नाम तक नहीं लिया जाता। भ्रष्टाचार–मुक्ति, स्वदेशी आर्थिकी, दुनिया में प्रभाव, चीन को झुकाना, और कृ एक आकस्मिक नया लक्ष्यरू श्कांग्रेस मुक्त भारत्थ और श्मॉं–बेटे को जेल पहुँचानाघ कृ यह सब अब भक्त भी नहीं दुहराते।

पूरे देश ने देखा कि चीन कहाँ है, और अपने राम क्या हैं। बगल बंगलादेश में हिन्दुओं का कत्ल, अपमान, मंदिर–ध्वंस होता रहा है कृ और अपने राजा के मुँह से एक शब्द तक नहीं निकला। जबकि कांग्रेस राज में बंगलादेश के हिन्दुओं के लिए संघ–परिवार यहाँ सरकार से दर्जन भर माँग करता था। उस में संयुक्त राष्ट्र में मु्का उठाना भी था!

यह उदाहरण है कि सारी बातें हवाबाजी थी। इसीलिए उन के कार्यकर्ता भी अब चुप हैं। सब जान चुके कि इन तिलों में तेल नहीं। कुछ विषयों में स्थिति पहले से बदतर हुई है। शिक्षा क्षेत्र इस का खुला उदाहरण है। विशिष्ट संस्थानों की स्वायत्तता भी छिन गई है। विद्या, विद्यार्थी, अध्यापक, स्नातक, सर्टिफिकेट या अवार्ड की गुणवत्ता का जिम्मेदार कोई नहीं है। महत्वपूर्ण अकादमियों में भी विद्वानों के स्थान पर मुंशी बिठा दिये गये हैं। ताकि अपनी टीम की जयकार करने, जुमले दोहराने वालों की संख्या बढ़े। बस! शिक्षा का जो हो, कुर्सी अपने हाथ रहे। यह फाउल खेलने जैसा है। पर उस से क्या, कैसे भी केवल चुनावी कप जीतते रहना है!

यह दूरघातक स्थिति है, जो अनेक संघ–भाजपाई भी मानते हैं। पर कहते हैंकृ क्या करें? यह मानसिक बदहाली इतनी व्यापक है कि किसी नीति, घोषणा, चुप्पी, बंदब स्थिति, आदि की आलोचना पर केवल यही कहते हैंकृ श्माजपा के हारने से आप को क्या मिलेगा?थ खाद्य अगले चुनाव में चार साल बाकी हो कृ पर उन के पास चुनाव छोड़ कोई विचार नहीं रह गया है। बारहों महीने उन्हें यही चिन्ता है। सो, अकेला लेखक भी यदि आलोचना करे तो वह चुनाव में हराने के लिए कर रहा है! अन्य कारण हो नहीं सकता किसी को नीति सुधार या नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं सूझती कि वह भी विचारणीय हो सकती है। जबकि वह लोकतंत्र में सब से सहज विचार है। ब्रिटेन में 2016 से 2022 के छरू वर्षों में एक ही सत्ताधारी दल के चार प्रधानमंत्रियों ने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया, सिर्फ यह देखकर कि उन की कोई नीति विफल रही या उन की लोकप्रियता कम हो गई। उन्हें पद छोड़ने की विवशता न थी! किन्तु उन्होंने अपने दल के अन्य नेता के लिए स्वयं स्थान छोड़ दिया। यह सच्ची समानता, साथीपन की भावना है। दलीय और राष्ट्रीय हित का सामंजस्य भी भारत में वह अकल्पनीय है! यहाँ शासक दूसरों को अपने से नीचा समझता है। आजीवन पद पर रहना अपना प्रथम अिहिकार मानता है। चाहे देश का कुछ भी मत या हाल हो। यह दलीय ढाँचा भी मात्र दिखावा होने का संकेत है। मुख्य बात केवल जैसे–तैसे गद्दी पर रहने, या गद्दी लेने की है। देश की चिन्ता कहीं पीछे या बिलकुल नहीं एक अर्थ में भयावह हाल है कि नेताओं के पास अपने किसी काम, निक्कमेपन, मनमानी, संसाधनों की बर्बादी, नीतिगत पलटी मारने, और चुप्पी के लिए दिखावटी दलील भी न हो! जिस का जगजाहिर सबूत वर्तमान शासकों द्वारा मीडिया का सामना न करना है। न अपने दल में किसी मतभेद स्वर का। ऐसे दलीय सहकर्मी भी किनारे कर दिये गये हैं।इस असाधारण दुर्बलता को छिपाने के लिए वे अनर्गल भाषणों का रेला दते रहते हैं, जहाँ कोई प्रश्नकर्ता न हो।



संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही डिलिमिटेशन का मुद्दा गरमाने लगा है। इस पर एनसीपी पवार गुट के सुरु अलग–अलग हैं। िधायक रोहित पवार ट्विट कर इस बिल का जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं और वहीं, सुप्रिया सुले इस बिल का कुछ हद तक समर्थन करती नजर आ रही हैं।

रोहित पवार ने ट्वीट कर कहा संसद के मानसून सत्र में ‘परिसीमन (निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन) विधेयक’ को पारित कराना ही सत्ताधारी पक्ष का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए मीठी बातें करके राज्यों को 50 प्रतिशत अधिक सीटें देने का लालच भी दिया जा सकता है। लेकिन यदि हम इन आंकड़ों के जाल में फंसकर इस विधेयक का समर्थन करते हैं, तो जिस तरह नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए वाड़ों का



पुनर्गठन किया गया, उसी तरह लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का भी राजनीतिक फायदे के लिए पुनर्गठन किया जाएगा। भौगोलिक सीमाओं या संवैधानिक मर्यादाओं की परवाह किए बिना केवल सत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से यह परिसीमन किया जाएगा और असम में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन इसका एक प्रमुख उदाहरण है।



सत्ता के समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने 2016 से ही अनुभवी पूर्व अधिकारियों की मदद से यह रणनीति तैयार कर रखी है कि किन–किन निर्वाचन क्षेत्रों का किस प्रकार पुनर्गठन किया जाए। अब उन्हें केवल इस विधेयक के पारित होने का इंतजार है। तब तक विपक्ष के साथ सौहार्द का दिखावा किया जाएगा, तरह–तरह के आश्वासनों का लालच दिया जाएगा, विपक्ष को विश्वास में लेने का नाटक किया जाएगा और लोकतंत्र की बातें भी की जाएंगी लेकिन जैसे ही यह विधेयक पारित होगा, विपक्ष को ऐसे किनारे कर दिया जाएगा, जैसे शरीर से पक्की झटक दी जाती है, और फिर से तानाशाही प्रवृत्ति हावी हो जाएगी। इसी प्रवृत्ति के तहत एक ओर परिसीमन और दूसरी ओर

करने वाली इंटरनेशनल साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत में श्कोंकरोघ शब्द और दिल्ली जंतर्–मंतर कनेक्शनर अब नए संदर्भ में अपरिचित नहीं रह गया है। सबसे पहले कुछ जमूनों ने अमेरिकी में बैठकर— भारत के युवाओं को— भारत के सुप्रिम कोर्ट की खलिाफत में ब्बातवंबी कहा। फिर भाजपा और मोदी विरोध की पटकथा लिखी गई। जबकि सुप्रिम कोर्ट के श्घ्र जरिस्टस सूर्यकांत ने मई 2026 में ये टिप्पणी फ्रीड्री डिट्री के जरिए वकालत करने वाले वकीलों पर की थी। इसका उन्होंने स्पटीकरण भी दिया था। लेकिन डीप स्टेट ने आम आदमी पार्टी के जमूरों को आगे कर — भारत की न्यायपालिका के खलिाफ उकसाया। यहीं से ब्बाा. तवंबी शब्द को भारत के युवाओं के माथे पर चस्पा करने की योजना को मूर्तकृ दिया गया।

आम आदमी पार्टी का जमूरा — दीपके भारत आया, झ्झर–उधर प्रदर्शन के लिए गया लेकिन धूप तक बर्दाश्त न कर पाया। तत्पश्चात श्ध्व के विरोध में सोनम गांगचुक को अमेरिकी मूल की उनकी पत्नी कृ रेबेका नॉर्मन के जरिए प्रोटेस्ट करे खाका बनाकर श्जंतर–मंतर के मैदान में भूख हड़ताल के लिए उतार दिया गया। जहां इमोशनली–सेंटीमेंट भुगाने के तमाम प्रयोजन रचे जाने लगे। नेपाल और बंगलादेश जैसे सत्ता की र्जिओम चेंज करने का खाका खींचा जाने लगा। फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताकच्च झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे



शरद पवार गुट भी दो राय आने लगी है। सांसद सुप्रिया सुले कही न कही इस बिल को समर्थन देने की तैयारी में हैं और बोल रही हैं कि अगर सरकार 50 फीसद वाले फार्मुले का लिखित दे, तो विचार किया जा सकता है, वहीं रोहित पवार विरोध कर रहे हैं। ‘ऑपरेशन टाइगर’ और एनसीपी अजित गुट में बढ़ते खींचतान की चर्चाओं के बीच अब

दंगे फैलाए जाएं। कन्वर्जन कराने वाले गिरोह के वो लोग जो श्ध्व की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम च एजेंसीज हायर की गई। सेलीब्रिटीज कहे जाने वाले कम्भी लोगकृ हिंदुत्व को ैजी करने के लिए उतर आए। विदेशी और देशी पैसें से सोशल मीडिया कैपेन को लॉन्च कर दिया गया। भावुक युवाओं ने भी देखा–सुनी ऐसी तमाम स्टोरीज सोशल मीडिया में शेयर की। जबकि इस तथाकथित आंदोलन में शिक्षाविद्, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स कहीं नजर नहीं आए। अगर स्टूडेंट्स नजर आए भी तो उन्हें मंच पर कहीं स्थान नहीं मिला। सिर्फ कुछ हाईलेक्स् , कॉमिडियन, नेता और भारत विरोधी –हिन्दुत्व विरोधी बातें कहने वाले चेहरे नजर आए। कंटेंट क्रिएटर्स ही दिखते रहे।

प्रोफेशनल चैंज्ज्स् में प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा हुआ। िथ्ेथ समेत तमाम गद्दार वामपंथियों का इकोसिस्टम एक्टिवेटड हुआ। श्श्रच्– ङ्च् की तर्ज पर अर्बन नक्सल गिरोह की जिहादी डफली सुनाई देने लगी। रूठठक्क का प्रचार–प्रसार किया जाने लगा। हिन्दू घ्रणा का परचम बुलंद किया जाने लगा। लेकिन इन जमूरों में से कोई भूख हड़ताल का साहस न कर पाया जिससे तंग आकर ख्बुद सोनम गांगचुक तक को ये कहना पड़ा किकृ “आप लोग यहाँ आकर दूस्–दूस् कर खा रहे हैं, मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है।”इतना ही नहीं ये जंतर्–मंतर वाले कॉंकरोघ — दिन के बाद रात को ऐसी रुम में जाकर सोते थे। घ्घार्टियां करने में जुट जाते थे। फिर अपने रूटीन में

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की एक कथित सीक्रेट बैठक ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पार्टी के भविष्य पर चर्चा हो रही थी तो शरद पवार के सबसे चर्चित युवा चेहरों में शामिल रोहित पवार उस बैठक से बाहर क्यों रहे? क्या उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया, या फिर इसके पीछे शरद पवार की कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिाकारिक जवाब नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है।सूत्रों के मुताबिक विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दौर में हुई इस बैठक में एनसीपी (शरद पवार गुट) के 10 में से 9 विधायक शामिल हुए। चर्चा इस बात पर हुई कि क्या पार्टी को अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होना चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि रोहित पवार इस बैठक में मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि अब इस पूरी कवायद को सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं, बल्कि पार्टी के भविष्य से जुड़े संभावित फैसले के तौर पर देखा जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान विधान भवन में एनसीपी (शरद पवार गुट) के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल ने पार्टी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई। बताया गया कि इस बैठक में रोहित पवार को छोड़कर बाकी नौ विधायक मौजूद थे। बैठक में व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अधिकांश विधायकों ने भाजपा के साथ सीधे गठबंधन करने और एनडीए का हिस्सा बनने की वकालत की। हालांकि इस संबंध में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बैठक में मौजूद नेताओं का मानना था कि विधायक शामिल हुए। चर्चा इस बात पर हुई कि क्या पार्टी को अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। विधायकों का तर्क था कि अगर केंद्र में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त सरकारी फंड चाहिए और 2029 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो सत्ता के साथ जाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।

बैठक में विधायकों की राय सुनने के बाद जयंत पाटिल ने कहा, ‘हमारे रुख पर राजनीतिक सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन अब ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है।’ इसके बाद उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि उनकी बात पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले तक विस्तार से पहुंचाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘एनडीए के साथ जाना निश्चित रूप से एक विकल्प है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय आदरणीय शरद पवार ही लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू, रोहित पवार की अनुपस्थिति रही। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भाजपा के साथ जाने के उनके कथित विरोधी रुख के कारण उन्हें बैठक से दूर रखा गया। हालांकि इसकी आधिकारिक प्ति है।

बैठक में विधायकों की राय सुनने के बाद जयंत पाटिल ने कहा, ‘हमारे रुख पर राजनीतिक सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन अब ठोस निर्णय लेने का समय आ गया है।’ इसके बाद उन्होंने विधायकों को भरोसा दिलाया कि उनकी बात पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले तक विस्तार से पहुंचाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ‘एनडीए के साथ जाना निश्चित रूप से एक विकल्प है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय आदरणीय शरद पवार ही लेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित पहलू, रोहित पवार की अनुपस्थिति रही। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भाजपा के साथ जाने के उनके कथित विरोधी रुख के कारण उन्हें बैठक से दूर रखा गया। हालांकि इसकी आधिकारिक प्ति है।



कार है, नीतियों पर प्रश्न उठाना स्वस्थ परंपरा है, किंतु राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बनाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। राजनीतिक मतभेद राष्ट्रभक्ति के स्थान पर नहीं आ सकते। राष्ट्र से ऊपर कोई दल, कोई नेता और कोई विवाधारा नहीं हो सकती। कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पर आक्षेप वास्तव में उन लाखों बलिदानों का अनादर है, जिनके कारण यह ध्वज आज स्वतंत्र आकाश में लहरा रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष किसी दल के लिए नहीं,

बल्कि इसी तिरंगे के सम्मान के लिए था। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उत्तरादायित्व भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान केवल औपचारिक अवसरों तक सीमित न रहे। यह हमारे व्यवहार, विचार और सार्वजनिक जीवन का स्थायी संस्कार बने। विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और उसके मूल्यों का समुचित अध्ययन कराया जाए। युवाओं को यह बताया जाए कि गणतंत्र केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराने वाला प्रेरक ध्वज है।

जंतर-मंतर के मुखौटों के पीछे का सच

श्रच् चतवजमेज।छप कृष्णमुशरी त्रिपाटी अटल । श्रनस 21 2026 4रू44रूड फिर मोदी विरोध के जितने भी इकोसिस्टम वाले चेहरे थे, वो सब बिल से बिलबिलाकर सामने आने लगे। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे भी करके दिल्ली में शाहीन बाग जैसे दंगे फैलाए जाएं। कन्वर्जन कराने वाले गिरोह के वो लोग जो श्ध्व की मार से चोटिल थे। उन्होंने जी भर के पैसे बहाए। तमाम च एजेंसीज हायर की गई।

चाहे छम्म्ज हो याकि कोई भी एग्जाम हो, जो भी स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं उन्हें कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। कोई भी दोषी बख्खो नहीं जाने चाहिए। किसी भी एग्जाम में जालसाजी, पेपरलीक जैसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने की संपूर्ण जवाबदेही सरकार की है। कोई व्यक्ति हो, संगठन हों। सबको अपनी–अपनी मांगों को लेकर विरोध करना चाहिए। आप इस्तीफा मांगिए। याकि जो भी संविधान सम्मत विरोध के शांतिपूर्ण तरीके हों, उन सबको करिए। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही भारत हैधे। संवाद के रास्ते हमेशा ही खुले होते चाहिए। सरकार का ये उत्तरदायित्व भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किकृ देश में अराजकता के संगठित कृत्य को आंदोलन कहकर स्वीकार कर लिया जाएगा। भारत के युवाओं को ब्बाातवंबी कहकर अपमानित

राष्ट्रीय ध्वज: राष्ट्र की अखंडता का अमर प्रतीक

ललित गर्ग ।
राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह केवल वर्तमान पीढ़ी का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय चेतना का आधार है। यदि किसी समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान कम होने लगे, तो धीरे–धीरे राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व भी कमजोर होने लगते हैं।

राष्ट्रीय ध्वज किसी भी राष्ट्र का सबसे गौरवपूर्ण प्रतीक होता है। वह केवल पूर्ण से सजा हुआ एक वस्त्र नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सामूहिक चेतना, उनके संघर्ष, उनके बलिदान, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य के सपनों का सजीव स्वरूप होता है। जब कोई राष्ट्र अपने ध्वज के सम्मानपूर्वक फहराता है, तब वह केवल एक झंडा नहीं लहराता, बल्कि हमारी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर हमारी राष्ट्रीय पहचान है और राष्ट्र हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित करता है। भारत में हर साल को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण यह है कि 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) को आिाकारिक रूप से अपनाया गया था। यह दिवस हमें अपने राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और

ध्वज रूपी प्रतीक—जैसे साहस, शांति और समृद्धि की याद दिलाता है। भारत का तिरंगा भी इसी गौरव, त्याग, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसकी प्रत्यक्ष लहराती हुई धारा स्वतंत्रता संग्राम के उन असंख्य ज्ञात–अज्ञात वीरों की स्मृति को जीवित करती है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर इस ध्वज को सम्मान दिलाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारे संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता में एकता की महान परंपरा का प्रतिनिधि है। भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं वाला विशाल देश है, लेकिन जब तिरंगा आकाश में लहराता है तो सारी विविधताएं एक राष्ट्रीय पहचान में समाहित हो जाती हैं। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह हमें यह स्मरण कराता है कि हमारी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर हमारी राष्ट्रीय पहचान है और राष्ट्र हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित करता है। भारत में हर साल को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण यह है कि 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगे) को आिाकारिक रूप से अपनाया गया था। यह दिवस हमें अपने राष्ट्रीय गौरव, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और

धारा अंतरिक्ष अभियानों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन—ये सभी दृश्य हमें यह अनुभव कराते हैं कि ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव की जीवंत अभिव्यक्ति है। भारतीय तिरंगे का प्रत्येक रंग अपने भीतर एक गहन संदेश समेटे हुए है। केसरिया रंग हमें त्याग, साहस और निस्वार्थ नेतृत्व की प्रेरणा देता है। यह बताता है कि राष्ट्र के निर्माण में व्यक्तिगत स्वाधैी का नहीं, बल्कि समर्पण और बलिदान का महत्व है। सफेद रंग सत्य, शांति और पारदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें जीवन और शासन दोनों में नैतिकता तथा सद्भाव बनाए रखने का संदेश देता है। हरा रंग समृद्धि, प्रकृति, कृषि और विकास का प्रतीक है, जो भारत की जीवनदायिनी वसती और उसके उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करता है। इन तीनों रंगों के म्थय स्थित गहरे नीले रंग का अशोक चक्र गतिशीलता, न्याय, धर्म और सतत प्रगति का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ठहराव मृत्यु है और निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है।राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वह केवल वर्तमान पीढ़ी का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राष्ट्रीय चेतना का आधार है। यदि किसी समाज में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान कम होने लगे, तो धीरे–धीरे राष्ट्रीय एकता,

सामाजिक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व भी कमजोर होने लगते हैं। राष्ट्र पहले भावनाओं से जुड़ता है, बाद में व्यवस्थाओं से। राष्ट्रीय ध्वज उन्हीं भावनाओं का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। दुर्भाग्य की बात है कि समय–समय पर कुछ सामाजिक और राजनीतिक तत्व अपने तात्कालिक स्वार्थी राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों या वैचारिक कटुता के कारण राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बना देते हैं। कभी राष्ट्रीय ध्वज को राजनीतिक मंचों पर अनावश्यक विवादों में घसीटा जाता है, कभी उसकी गरिमा को कम करने वाले वक्तव्य दिए जाते हैं और कभी उसे केवल दलगत दृष्टि से देखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रवृत्ति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक किसी दल, सरकार या विवाधारा के नहीं होते, वे पूरे राष्ट्र की साझा धरोहर होते हैं। सरकारें बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल आते–जाते रहते हैं लेकिन राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संविधानिक आधारशिला है। उसे उखाड़ फेंकने की बातें दुहराई गईं। भारत को श्नेपालश



कार है, नीतियों पर प्रश्न उठाना स्वस्थ परंपरा है, किंतु राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, संविधान और अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद का विषय बनाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। राजनीतिक मतभेद राष्ट्रभक्ति के स्थान पर नहीं आ सकते। राष्ट्र से ऊपर कोई दल, कोई नेता और कोई विवाधारा नहीं हो सकती। कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पर आक्षेप वास्तव में उन लाखों बलिदानों का अनादर है, जिनके कारण यह ध्वज आज स्वतंत्र आकाश में लहरा रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष किसी दल के लिए नहीं,

बल्कि इसी तिरंगे के सम्मान के लिए था। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि ऐतिहासिक उत्तरादायित्व भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान केवल औपचारिक अवसरों तक सीमित न रहे। यह हमारे व्यवहार, विचार और सार्वजनिक जीवन का स्थायी संस्कार बने। विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास और उसके मूल्यों का समुचित अध्ययन कराया जाए। युवाओं को यह बताया जाए कि गणतंत्र केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराने वाला प्रेरक ध्वज है।

आजमगढ़ के नए ARTO कार्यालय के स्थानांतरित होने से लोगों में असंतोष, ARTO विष्णु दत्त मिश्रा ने दिया व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा

आजमगढ़। जनपद में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) के



जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थानांतरित होने से आम जनता और क्षेत्र में हलचल मच गई है। आजमगढ़ शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित इस नए कार्यालय पर किलहाल कोई स्पष्ट पहचान चिह्न या दिशा—सूचक बोर्ड न होने के कारण यहाँ पहुँचने वाले लोगों को काफी असमंजस और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मामले पर जानकारी देते हुए एआरटीओ विष्णु दत्त मिश्रा ने बताया कि नए परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ तेजी से जुटाई जा रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सहूलियत के लिए जल्द ही जगह—जगह साइन बोर्ड लगाए जाएँगे और आवागमन के साधनों को भी सुचारु किया जाएगा। विभाग का दावा है कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कर जनता को राहत पहुँचाई जाएगी।

‘मन के मौसम’ काव्य संग्रह का विमोचन, पर्यटन मंत्री बोले- नारी मन की संवेदनाओं का सशक्त दस्तावेज है पुस्तक

लखनऊ, (संवाददाता) उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को पर्यटन भवन के सभागार में लेखिका रुचि चौहान के प्रथम काव्य संग्रह ‘मन के मौसम’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने लेखिका को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह काव्य संग्रह नारी मन की कोमल भावनाओं, संवेदनाओं और जीवन के विविध अनुभवों का सशक्त साहित्यिक दस्तावेज है, जो समाज विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।पर्यटन मंत्री ने कहा कि ‘मन के मौसम’ में नारी हृदय की सूक्ष्म भावनाओं, मिलन, वियोग, पीड़ा, संघर्ष, शोषण और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं को अतृप्त सरल एवं प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि लेखिका का शब्द चयन सराहनीय है और कई कविताओं में भावनाएँ शब्दों के साथ सहज रूप से बहती हुई प्रतीत होती हैं।

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक सम्पन्न, चढ़ावा व्यवस्था, मुख्य पेपर लीक और छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में संसद परिसर में सपा का कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और श्रावण मेले की तैयारियों पर मंयन

लखनऊ (संवाददाता)। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को अयोध्या में आयोजित हुई। बैठक में आगामी श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए दर्शन व्यवस्था, मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति तथा अन्य प्रशासनिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही न्यासी मंडल में रिक्त पदों की पूर्ति और विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।बैठक में चढ़ावा राशि की गणना प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट को भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण

इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। न्यास ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिकाओं की सुनवाई की प्रगति और न्यायालय के निर्देशों का भी संज्ञान लिया।न्यासियों ने मंदिर परिसर में पहले से उपलब्ध करा दी गई है। इससे सुख्खा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो रही हैं।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान की टकसाल के साथ चर्चण एवं रजत चढ़ावे की शुद्धता जांचने तथा उनके प्रबंधन की

व्यवस्था पहले की तरह निरंतर जारी रहेगी। न्यासी मंडल ने इस व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।चढ़ावा राशि के प्रबंधन को लेकर भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए समझौते के अंतर्गत बैंक की जिम्मेदारियों और उनके निर्वहन में सामने आई त्रुटियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। न्यासी मंडल ने इस मामले में बैंक की प्रतिक्रिया और अपेक्षित गंभीरता के अभाव पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद न्यास की वित्त समिति को बैंक के साथ भविष्य के संबंधों और मानक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए।बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। चयन समिति ने बताया कि इस पद

के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके कारण सभी आवेदनों का गहन परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। समिति ने चयन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा, जिससे विषय की गंभीरता को देखते हुए स्वीकार करने पर विचार किया गया।न्यास ने स्पष्ट किया कि श्रीराम मंदिर से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता, सुख्खा और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी श्रावण मास में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पेपर लीक, छात्रों के कथित उत्पीड़न और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार पर आयोजित विरोध—प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए

अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छात्र, नौजवान और उनके परिवार पेपर लीक की घटनाओं तथा सरकार के रवैये से आहत हैं। उनका कहना था कि छात्र लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटा रही है।अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। उनका आरोप था कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे कई छात्र घायल हुए और छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ।उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देशभर में 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाएँ हो चुकी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश

में ही 20 से अधिक भर्ती और परीक्षा संबंधी प्रश्नपत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं। उनके अनुसार इससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है।समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष और छात्र—युवाओं की मांगें समान हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, छात्रों के साथ हुई कथित घटनाओं की जवाबदेही तय करने और सरकार द्वारा छात्रों से संवाद स्थापित करने की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं,

किसानों और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की है तथा महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।संसद में अपनी बात रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की बात नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन और तेज होगा। उनका कहना था कि सरकार को पहले छात्रों के साथ हुई घटनाओं का जवाब देना चाहिए।



ओमैक्स सिटी चोरीकांड का खुलासा, बिजनौर पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा, चोरी का सामान और नकदी बरामद

लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी करने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को ओमैक्स सिटी निवासी गरिता सिंह ने बिजनौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में दो विशेष पुलिस टीमां का गठन किया गया। टीमां ने आसपास लगे लगभग 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साध्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार को औरंगाबाद अंडरपास से न्यू गुड्रौ जाने वाली शहीद पथ की सर्विस रोड से सुनील (41 वर्ष) निवासी कठौता, थाना विभूतिखंड को गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को बायोऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी सभागार में भारत बायोऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी—2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, निवेश की संभावनाओं, उद्योगों की भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अंबवीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल,

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (एपीनैडा) के निदेशक रविंद्र सिंह, सचिव पंकज सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जनत के प्रतिनिधि I, बायोऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अन्य संबंधित पक्ष उपस्थित रहे।बैठक को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शनी प्रदेश को बायोऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित जैव गैस, एथेनॉल, जैव डीजल, टिकाऊ विमान ईंधन, कचरे से ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य हरित तकनीकों के क्षेत्र में

वैश्विक पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगी।उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उत्तर प्रदेश के पास कृषि अवशेष का विशाल भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 17 मिलियन टन कृषि अवशेष में से केवल 5 मिलियन टन का ही उपयोग हो रहा है। यदि इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए तो प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।ऊर्जा उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्देश्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश को बायोऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस क्षेत्र में लगातार प्रगती

प्रयास किए जा रहे हैं तथा समय की आवश्यकता के अनुरूप नीतियों को और अधिक मजबूत एवं अद्यतन बनाया जाएगा।उन्होंने सभी विभागों, उद्योग संगठनों और संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करते हुए आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का आह्वाण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी प्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को नई गति देगी तथा उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।बैठक में बताया गया कि 11 से 13 अगस्त 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित भारत प्रदर्शनी केंद्र एवं प्रांगण में यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश नवीन एवं

नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण तथा भारतीय हरित ऊर्जा महासंघ को सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश—विदेश के नीति निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योगपति, निवेशक और ऊर्जा विशेषज्ञ भाग लेंगे।आयोजन के दौरान 25 से अधिक विचार—विशर्ष सत्र आयोजित होंगे। 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय वक्ता अपने विचार रखेंगे, 150 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे तथा हजारों प्रतिनिधियों और व्यावसायिक आगंतुकों के शामिल होने की संभावना है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा और बायोऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पुलिस मुख्यालय की पैनी नजर, डीजीपी राजीव कृष्ण ने कंट्रोल रूम से संभाला मोर्चा



रखें और आमजन से संवाद बनाए रखते हुए शांति एवं सौहार्द का वातावरण कायम रखें।डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार में शांति, सुख्खा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल और संसाधन भी तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि प्रदेश में पूरी तरह शांति और सामान्य जनजीवन बना रहे।

लखनऊ(संवाददाता)। प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय लगातार सक्रिय है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से प्रदेशभर की सुख्खा व्यवस्था और मौजूदा हालात की गहन समीक्षा की। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अमिताभ यश सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और प्रदेश के विभिन्न जिलों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी।पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर स्थिति की जानकारी ली जा रही है। जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर कानून व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा—निर्देश जारी किए जा रहे हैं।वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी पुलिस आयुक्तों, परिक्षेत्रीय अधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा किसी भी परिस्थिति से तत्काल और प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए हैं।पुलिस मुख्यालय द्वारा सशाल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली गतिविधि यों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि अफवाहों पर कड़ी नजर

प्रदर्शन, अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई



आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है।पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई 2026 को शोभित सरन ने आशियाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जून की रात करीब 9रु47 बजे वह अपनी पत्नी को किक्सिकस के यहां से दिखाकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मानसरोवर योजना स्थित पार्क संख्या—10 के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बदमाश उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। शिकायत के आधार पर आशियाना थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य तकनीकी साधनों के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 21 जुलाई की रात करीब 11रु30 बजे सभाबाई अखंडकर मैदान रैली स्थल रोड से राज रावत (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया।फूफ्फाछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने खर्च पूरे करने के लिए रात के समय मेबाइल और रसोई की रस झपटने की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन का लगभग 1.680 ग्राम वजन का टुकड़ा बरामद किया है।बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की एक और धारा बढते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिज्ञा में जेल भेज दिया गया।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राज रावत, रायबरेली रोड स्थित ईश्वरी खेड़ा का निवासी है और उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध पीजीआई और सुरक्षा गुरुफ सिटी थानों में लूट, चोरी तथा चोरी के माल की बरामदगी सहित कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अन्य थानों से भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटा रही है।

लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र स्थित ओमैक्स सिटी में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी करने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी और अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को ओमैक्स सिटी निवासी गरिता सिंह ने बिजनौर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर उनके बंद मकान का ताला तोड़कर घर में रखे जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।घटना के खुलासे के लिए पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में दो विशेष पुलिस टीमां का गठन किया गया। टीमां ने आसपास लगे लगभग 40 से 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का गहन विश्लेषण किया। तकनीकी साध्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने बुधवार को औरंगाबाद अंडरपास से न्यू गुड्रौ जाने वाली शहीद पथ की सर्विस रोड से सुनील (41 वर्ष) निवासी कठौता, थाना विभूतिखंड को गिरफ्तार कर लिया।

लखनऊ,(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश को बायोऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लखनऊ स्थित इन्वेस्ट यूपी सभागार में भारत बायोऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी—2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने की। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, निवेश की संभावनाओं, उद्योगों की भागीदारी तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अंबवीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आशीष गोयल,

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (एपीनैडा) के निदेशक रविंद्र सिंह, सचिव पंकज सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जनत के प्रतिनिधि I, बायोऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं अन्य संबंधित पक्ष उपस्थित रहे।बैठक को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शनी प्रदेश को बायोऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, संपीड़ित जैव गैस, एथेनॉल, जैव डीजल, टिकाऊ विमान ईंधन, कचरे से ऊर्जा उत्पादन तथा अन्य हरित तकनीकों के क्षेत्र में

वैश्विक पहचान दिलाने का सशक्त माध्यम बनेगी।उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण उत्तर प्रदेश के पास कृषि अवशेष का विशाल भंडार उपलब्ध है। वर्तमान में लगभग 17 मिलियन टन कृषि अवशेष में से केवल 5 मिलियन टन का ही उपयोग हो रहा है। यदि इसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाए तो प्रदेश हरित ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।ऊर्जा उभर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्देश्य केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तर प्रदेश को बायोऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस क्षेत्र में लगातार प्रगती

प्रयास किए जा रहे हैं तथा समय की आवश्यकता के अनुरूप नीतियों को और अधिक मजबूत एवं अद्यतन बनाया जाएगा।उन्होंने सभी विभागों, उद्योग संगठनों और संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करते हुए आयोजन को ऐतिहासिक और सफल बनाने का आह्वाण किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी प्रदेश में निवेश, रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और सतत विकास को नई गति देगी तथा उत्तर प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।बैठक में बताया गया कि 11 से 13 अगस्त 2026 तक ग्रेटर नोएडा स्थित भारत प्रदर्शनी केंद्र एवं प्रांगण में यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश नवीन एवं

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की सपा सांसद डिंपल यादव ने की निंदा, बोलीं- समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रहेगी

नई दिल्ली।धूलखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों और नौजवानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए।संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि पूरे देश ने देखा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में छात्रों को गंभीर चोटें आईं और छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ।उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर भाजपा सरकार की नीयत ठीक नहीं दिखती। उनके अनुसार छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की तस्वीरों ने पूरे देश को दुखी किया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार रामराज्य की बात करती है, तो उसे छात्रों और युवाओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए।डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसान, युवा, छात्र और समाज का हर वर्ग परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनके आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है।सपा सांसद ने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुई घटना लोकतंत्र के लिए किताजरनक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध—प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों के प्रति पुलिस और सरकार के रवैये की निंदा करती है तथा युवाओं के अधिकारों और न्याय की लड़ाई आगे भी मजबूती से लड़ती रहेगी।

आशियाना में चेन स्नेचिंग का खुलासा, पुलिस ने शातिर लुटेरे को दबोचा, छिनी गई सोने की चेन का हिस्सा बरामद



लखनऊ(संवाददाता)। राजधानी के आशियाना क्षेत्र में महिला से चेन छीनने की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन का एक हिस्सा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी लूट और चोरी की कई घटनाओं में जेल जा चुका है तथा उसके

जैकब बेयेल घुटने की चोट के कारण द हंड्रेड से बाहर



नई दिल्ली , । दाहिने घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल इस साल श्व द हंड्रेड्स टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। इस उभरते हुए खिलाड़ी को बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी का एक अहम मौका नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ बेथेल के अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है। बर्मिंघम फीनिक्स ने शुक्रवार को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ ओपनिंग मैच के लिए बेथेल की जगह साउथ अफ्रीका के डेनोवन फेररा को कप्तान चुना है। फ्रेंचाइजी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान की फिटनेस पर भी नजर रख रही है, जो हाल ही में इंटरनेशनल ज़ूट्टी के दौरान लगी चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं। बेथेल भारत के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। सोमवार सुबह एमआरआई स्कैन के बाद उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बेथेल के फिट होने में लगने वाले समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

पाकिस्तान को खिलाफ इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को हेडिंघले में शुरू होगा। सीरीज के अगले दो मुकाबले 27 अगस्त और 9 सितंबर से खेले जाएंगे। ईसीबी ने एक बयान में कहा, जैकब बेथेल दाहिने घुटने की चोट के कारण श्व द हंड्रेड्स से बाहर हो गए हैं। उन्हें मेट्रो बैंक वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और कल सुबह उनका एमआरआई स्कैन हुआ था। वह अपना रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे और हम जरूरत के हिसाब से अपडेट देते रहेंगे।

अपनी निराशा जाहिर करते हुए बेथेल ने कहा, द हंड्रेड से बाहर होना निराशाजनक है, खासकर एजबेस्टन में अपने फैंस के सामने बर्मिंघम फीनिक्स का प्रतिनिधित्व करने का मौका चूकना। दुर्भाग्य से, मुझे पूरी तरह

एक्स यूजर्स की हो गई मौज, कंपनी ने लान्व किया बिल्कुल नया एंड्रायड ऐप, अब सुपरफास्ट स्पीड में दौड़ेगा अकाउंट



नई दिल्ली । अगर आप भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ड्रग (पहले ट्विटर) का इस्तेमाल करते हुए स्लो स्पीड, लिंक न खुलने और बार–बार हैंग होने जैसी समस्याओं से परेशान थे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सालों की शिकायतों के बाद आखिरकार कंपनी ने अपने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ड्रग ऐप का बिल्कुल नया और दमदार वर्जन रिलीज कर दिया है। इसे सिर्फ एक सामान्य अपडेट की तरह पेश नहीं किया गया है, बल्कि जड़ से दोबारा बनाया गया है ताकि आपको सुपरफास्ट स्पीड, शानदार नोटिफिकेशन अलर्ट और मखन जैसी स्मूथ स्क्रीनिंग का बेहतरीन अनुभव मिल सके। यह नया ऐप गूगल प्ले स्टोर (नशशहददग्द वकइड्ड्द स्ल्लशहदद्ग्द) पर दुनिया भर के यूजर्स के लिए डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो चुका है जड़ से खत्म की गई पुरानी समस्याएं

कंपनी के मुताबिक, इस नए एंड्रॉयड ऐप को धीरे-धीरे अपडेट करने के बजाय एकदम बेसिक स्तर (शुरु से) से उ्खल किया गया है। ड्रग का कहना है कि इसके नए आर्किटेक्चर को तैयार करने का मुख्य मकसद लंबे समय से चली आ रही परफॉर्मिा की समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करना है। पिछले साल एंड्रॉयड यूजर्स को ऐप चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ था, जिनमें स्लो लोडिंग और शेयर्ड लिंक से फेस्ट लोड न होने जैसी कमियां शामिल थीं। अब नए डिजाइन के साथ भविष्य में नए फीचर्स को जोड़ना भी काफी आसान हो जाएगा।

विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटाने की तैयारी, भारत तेज करेगा डीप वाटर पोर्ट परियोजनाएं



नई दिल्ली । भारत प्रमुख बंदरगाहों के अपग्रेड और नए गहरे समुद्री टर्मिनलों के निर्माण में तेजी ला रहा है, ताकि वर्तमान में कोलंबो और सिंगापुर के जरिए होने वाले ट्रांसशिपमेंट यातायात को अपने यहां आकर्षित किया जा सके। यह जानकारी एक नई रिपोर्ट में सामने आई।इंडिया नैरेटिव की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार चेन्नई के निकट एन्नोर स्थित कामराजपुर बंदरगाह, ओडिशा के पारदादीप बंदरगाह और कच्छ के दीनदयाल बंदरगाह सहित कई प्रमुख बंदरगाहों की ड्रापट (जल की गहराई) को 14 मीटर से बढ़ाकर 18 मीटर कर रही है, ताकि वे बड़े मंदर वेसल (मुख्य मालवाहक जहाज) को संभाल सकें। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज (मंदर वेसल) एमएससी

फिट होने के लिए समय चाहिए। अब मेरा ध्यान अपना रिहैबिलिटेशन पूरा करने और पूरी तरह फिट होकर वापसी करने पर है।

21 वर्षीय खिलाड़ी को बर्मिंघम फीनिक्स ने 3,40,000 पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट पर रिटैन किया और 2026 सीजन के लिए कप्तान बनाया था। इस फ्रेंचाइजी की संयुक्त मालकिन वार्विकशायर और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड नाइटहेड कैपिटल है। इंग्लैंड के फुटबॉल स्टार जूड बेलिंगहम भी इसमें स्टेकहोल्डर हैं।

बेथेल को इंग्लैंड के भविष्य के लीडर्स में से एक माना जाता है। पिछले साल जब बीबी ब्लैक को आराम दिया गया था, तब बेथेल ने आयरलैंड में टीम को टी20 सीरीज जिताई थी। उन्हें बतौर टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का संभावित उत्तराधिाकारी भी माना जाता है। अगर ब्लैक टेस्ट टीम की कप्तानी संभालते हैं तो बेथेल व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में एक विकल्प हो सकते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उंगली की चोट के कारण गर्मी के मौसम की मुश्किल शुरुआत के बाद, बेथेल ने बेहतरीन फॉर्म वापस हासिल करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 74 रन बनाए थे, उन्होंने भारत के विरुद्ध दूसरे टी20 मुकाबले में नाबाद 76 रन की पारी खेली, और वनडे सीरीज के फाइनल मैच में 91 रन बनाने के साथ 49 रन देकर 1 विकेट लेकर श्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीता था।

अईफोन (दबल्स) को सीधे टक्कर देने की तैयारी

एंड्रॉयड ऐप को पूरी तरह से बदलने की यह शुरुआत पिछले साल तब हुई थी, जब ड्रग प्रबंधन ने खुद यह स्वीकार किया था कि उनका एंड्रॉयड वर्जन आईफोन (दबल्स) वर्जन की तुलना में काफी पीछे रह गया है। इस भारी अंतर को मिटाने के लिए कंंपनी ने एक खास शर्डिंकटेड एंड्रॉयड इंजीनियरिंग टीम्व का गठन किया था। ड्रग के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने इसे कंंपनी के सबसे बड़ेइंजीनियरिंग प्रोजेक्त्स में से एक बताया है। उन्होंने दावा किया है कि इस नए ऐप में यूजर्स को बेहद स्मूथ नैविगेशन, डाटके से पेज लोड होने की स्पीड और पहले से कहीं बेहतर रिसर्प्स मिलेगा।

भविष्य में आने वाले हैं कई और धांसू फीचर्स

भले ही ड्रग का यह नया और तेज ऐप लॉन्च हो गया है, लेकिन कंंपनी का कहना है कि इसे और ज्यादा परफेक्ट बनाने का काम अभी भी जारी है। कंंपनी की योजना पुराने और कम चैम वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर भी इसकी परफॉर्मिा को सुधारने और इसके लोकप्रिय लाइव ऑडियो फीचर रस्पेसेसव (रस्चड्डुग्दगह) के लिए बेहतरीन सपोर्ट जोड़ने की है। इसके अलावा, आने वाले दिनों में एंड्रॉयड यूजर्स को नया वीडियो एडिटर, वीडियो रिएक्शन, कैशटेगे (ष्टड्डहदहदहइड्डह) और कस्टम टाइमलाइन जैसे कई शानदार फीचर्स भी मिलने वाले हैं, जो ड्रग के बड़े प्रोडक्ट रोडमैप का अहम हिस्सा हैं।

सिडनी , । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने बुधवार को सिडनी की एक कोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में कोर्ट 18 अगस्त को सजा सुनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की घरलू टी20 लीग बिग बैश (बीबीएल) मेंसिडनी थंडर फ्रेंचाइजी की कमान संभाल रहे वॉर्नर कोर्ट की कार्रवाई के दौरान खुद पेश नहीं हुए। इसके बजाय, डेविड वॉर्नर की ओर से उनके वकील बॉबी हिल सिडनी की अदालत में पेश हुए और उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में औपचारिक रूप से अपना दोष स्वीकार किया। यह मामला 5 अप्रैल, ईस्टर रविवार का है, जब वॉर्नर एक वैन चला रहे थे। वह एक जगह पर रुके, जो यादृच्छिक श्वास परीक्षण बिंदु से थोड़ी दूरी पर थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने सड़क किनारे उनका श्वास टेस्ट किया। जांच में उनके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तय कानूनी सीमा

चेल्सी फुटबाल क्लब से जुड़े इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मार्गन रोजर्स, 7 साल का हुआ करार

लंदन , । चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी मॉर्गन रोजर्स को एस्टन विला से साइन कर लिया है। प्रीमियर लीग क्लब ने कहा कि 23 साल के खिलाड़ी ने 2033 तक स्टैमफोर्ड ब्रिज में रहने के लिए सात साल की डील साइन की है। चेल्सी ने निडफील्डर को कथित तौर पर 117 मिलियन पाउंड की डील पर साइन किया है, जिससे यह अब तक के सबसे महंगे ब्रिटिश खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस गर्मी की शुरुआत में इलियट एंडरसन के 116 मिलियन पाउंड में मैनचेस्टर सिटी में शामिल होने का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लब द्वारा जारी एक बयान में रोजर्स ने कहा, मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरे लिए चेल्सी लंदन का सबसे बड़ा क्लब है और एक ऐसा क्लब है जिसकी मैं बचपन से तारीफ करता रहा हूं। मैं नए मैनेजर के साथ प्रोजेक्ट हमारे पास मौजूद खिलाड़ियों और क्लब

अब बिना इंटरनेट के भी घड़ाघड़ होगा यूपीआई पेमेंट, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप



नई दिल्ली । आम लोगों के लिए यूपीआई से जुड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब वह दिन दूर नहीं जब आप बिना इंटरनेट के भी अपना यूपीआई पेमेंट आसानी से कर सकेंगे। सामने आए कहा गया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जल्द ही एक ऐसी यूनिकाइड पेमेंटस इंटरफेस (क्कदूद) सुविधा शुरू होने जा रही है, जिसकी मदद से ग्राहक

से दोगुनी से भी ज्यादा पाई गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने ले गई। वॉर्नर के वकील बॉबी हिल ने इस साल की शुरुआत में एक सुनवाई के दौरान कहा था, हम में से बहुत से लोग ऐसे गलत फैसले लेते हैं। मुझे लगता है कि उन गलत फैसलों को मानना और उनके लिए जवाबदेह होना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक ट्रेड्समैन हैं एक डॉक्टर हैं या दुनिया के सबसे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन में से एक हैं यह खतरा हम सभी के लिए मौजूद है। वह जानते हैं कि उन्होंने जो किया वह गलत था। वह मानते हैं कि यह एक लापरवाही भरा फैसला था, उबर लेने के बजाय अपनी कार में बैठना एक बेवकूफी भरा फैसला था।कोर्ट ने इस मामले में अंतिम सजा सुनाने के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है। वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में स्थानीय ट्रैफिक कानूनों के तहत

की दिशा को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इसी वजह से मैं यहां हूं और क्लब की तरफ से खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।आर्सनल ने इस ट्रांसफर विंडो में मॉर्गन रोजर्स को अपनी पहली पसंद के फॉरवर्ड के रूप में देखा था। हालांकि, क्लब ने उतनी ट्रांसफर फीस देने से इनकार कर दिया, जितनी प्रीमियर लीग 2025–26 चैंपियन चेल्सी देने के लिए तैयार थी। इसलिए आर्सनल इस डील को पूरा नहीं कर सका।चेल्सी से जुड़ने से पहले मॉर्गन रोजर्स ने खुद को प्रीमियर लीग के सबसे प्रतिभाशाली युवा अटैकिंग खिलाड़ियों में शामिल कर लिया है। एस्टन विला के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और 85 प्रीमियर लीग मैचों में गोल और असिस्ट मिलाकर 40 गोल में योगदान दिया। उनके दमदार खेल की बदौलत टीम पिछले सीजन में प्रीमियर लीग के शीर्ष चार में जगह बनाने में सफल

सजा का सामना करना पड़ सकता है। उनके दोष स्वीकार करने के बाद आगामी बिग बैश लीग (बीबीएल) सीजन में सिडनी थंडर के कप्तान के रूप में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

मौजूदा नियमोंके अनुसार, वॉर्नर पर कम से कम छह महीने के लिए ड्राइविंग प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन पर 2,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है और गंभीर स्थिति में उन्हें अधिकतम नौ महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है।क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) के मुख्य कार्यकारी ली जर्मन ने वॉर्नर की गिरफ्तारी के बाद कहा था कि ये आरोप बेहद गंभीर हैंऔर संगठन इन्हें पूरी गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा, क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स हमेशा सुरक्षित ड्राइविंग का समर्थन करता है और शराब पीकर गाड़ी चलाने के पूरी तरह खिलाफ है। सिडनी थंडर,



सिडनी सिक्सर्स और एनएसडब्ल्यू ब्लूज भी शराब पीकर गाड़ी चलाने को रोकने के लिए राज्य सरकार के जागरूकता अभियान का हिस्सा हैं और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं।



त्व किया, जहां थॉमस ट्यूशेल की टीम तीसरे स्थान पर रही। 1966 में विश्व कप जीतने के बाद यह इंग्लैंड का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

अब बिना इंटरनेट के भी घड़ाघड़ होगा यूपीआई पेमेंट, आ रहा है ये धांसू फीचर, जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप

उन जगहों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो उपलब्ध नहीं होती या फिर बिल्कुल भरोसेमंद नहीं होती है। इसमें हवाई जहाज के कॅबिन से लेकर अंडरग्राउंड ट्रेन नेटवर्क और दूरदराज के इलाक़े शामिल हैं। इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी होने पर पहले अपने डिवाइस के यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे लोड करने होंगे। इसके बाद जब वे ऑफलाइन होंगे, तो बिना किसी यूपीआई पिन के टर्मिनल पर टैप करके आसानी से उस बैलेंस का इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर सकेंगे।एनएफसी तकनीक से ऐसे पूरा होगा आपका ऑफलाइन ट्रांजेक्शन।नेशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (इक्कटददद) साल

2026 में प्रमुख टर्मिनल बनाने वाली कंपनियों के पीओएस डिवाइस को इस नई सुविधा के लिए सर्टिफाई करना शुरू कर सकता है। इस पूरी प्रस्तावित व्यवस्था में नियर–फील्ड कम्युनिकेशन (ह्र्सन्चट) तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत ग्राहकों को अपने एनएफसी इनेबल्ड फोन को सिर्फ ऑफलाइन टर्मिनल पर टैप करना होगा और वे बिना रुके 2,000 रुपये तक का पेमेंट चुटकियों में कर सकेंगे। जब डिवाइस ऑफलाइन होगा तब पीओएस मशीन पेमेंट ऑथराइजेशन को अपने पास स्टोर कर लेगी और जैसे ही कनेक्टिविटी वापस आएगी, उसे नेटवर्क पर आगे प्रोसेस कर देगी।यूपीआई लाइट एक्स से कैसे अलग है यह नई व्यवस्था आपको बता दें कि एनपीसीआई द्वारा एनएफसी का यह कोई पहला

सोने-चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 24 कैरेट गोल्ड 1.43 लाख के पार, खरीदने से पहले जान लें लेटेस्ट रेट



सुबई । सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। इससे दोनों कीमती धातुओं का दाम क्रमशः 1.43 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.23 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गया है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के

मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 883 रुपए या 0.61 प्रतिशत दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। 1.42,254 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,305 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,31,113 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं, 18 कैरेट सोने का

दाम 1,06,691 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,07,353 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी तेजी देखी गई है। चांदी का दाम 3,629 रुपए या 1.65 प्रतिशत बढ़कर 2,23,204 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो कि पहले 2,19,575 रुपए प्रति किलो था।

मल्टी कंमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक सोने का 5 अगस्त, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.82 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,42,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी का 4 सितंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 2.13 प्रतिशत की मजबूती के साथ 2,23,057 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोना 1.22 प्रतिशत की मजबूती के साथ 4,064 डॉलर प्रति औंस और चांदी 3.54 प्रतिशत की तेजी के साथ 59 डॉलर प्रति औंस पर था।जानकारों ने कहा कि इस तेजी के वजह अमेरिका–ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। आने वाले समय में सोना 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से लेकर 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकता है।

